



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 अक्टूबर, 2022 ई०

कार्तिक 06, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-6

संख्या 197/XXVII(6)/1466/तीन/2022

देहरादून, 28 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प० आ०-102

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखापरीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 2 वर्ष 2012) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड आंतरिक लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2021 के नियम 6 एवं नियम 7 के खण्ड (ख) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एवं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट (INTOSAI) के संगठन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा सिद्धांतों एवं मानकों को राजस्व लेखा परीक्षा हेतु लागू किए जाने के लिए निम्नलिखित नियम संग्रह बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

### उत्तराखण्ड राजस्व लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2022

संक्षिप्त विस्तार और प्रारंभ	नाम,	1. (1) इस लेखापरीक्षा नियम संग्रह का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2022 है।
------------------------------	------	--

(i) यह उन समस्त ऑडिटी पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 495/XXVII(11)/2012, दिनांकित 26 नवंबर, 2012 के माध्यम से लागू उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 4 की उपधारा (1) के क्रम में अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) राजस्व लेखापरीक्षा के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समस्त कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियाँ की लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

(iii) निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा हेतु कार्यरत कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा या संनदी लेखाकार/फर्म या संस्था (एजेंसी) जिसे वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निदेशालय लेखापरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया हो, राजस्व अर्जन विभागों की लेखापरीक्षा किये जाने के समय संबंधित लेखापरीक्षा नियम संग्रह का प्रयोग किया जायेगा।

(iv) यह उत्तराखण्ड आंतरिक लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2021 एवं विशिष्ट कार्य क्षेत्रों के लेखापरीक्षा नियम संग्रह यथा निष्पादन लेखापरीक्षा नियम संग्रह, धोखाधड़ी और न्याय सम्बंधी लेखापरीक्षा नियम संग्रह, सूचना प्रौद्यौगिकी लेखा प्रौद्यौगिकी लेखापरीक्षा नियम संग्रह के साथ पढ़ा जाएगा।

(v) यह मुख्यतः उदग्रहण, संग्रहण, अपवंचन, विभिन्न मांगों का लक्ष्य, कर निर्धारण, आन्तरिक नियंत्रण का आंकलन प्रतिदाय, छूट जैसं संबंधितः क्षेत्रों पर केंद्रित है।

(3) यह अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

## राजस्व लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य

2. राजस्व लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

(i) राजस्व निर्धारण, राजस्व संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विनियम और आंतरिक प्रक्रियाएँ सौजूद हैं।

(ii) लागू विनियमों और प्रक्रियाओं को विभागों द्वारा कार्यान्वित और अपनाया गया है।

(iii) विभाग द्वारा अधिनियम और नियमों/नियम संग्रह के प्रावधानों में उल्लिखित समय सारणी के

अनुसार राजस्व आंकलन, संग्रहण और लेखांकन किया गया है।

(iv) अधिनियम और नियमों/नियम संग्रह के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिदाय एवं छूट प्रदान की गई है।

(v) राजस्व विभागों में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण।

(vi) राजस्व विभाग द्वारा नवीन तकनीकी के अनुप्रयोग एवं नवीन तकनीकी प्रयोग में सामान्य एवं तकनीकी नियंत्रण की प्रस्तुति।

उत्तराखण्ड राजस्व लेखापरीक्षा नियम संग्रह के खंड एवं संबंधित खंडों में संक्षिप्त विवरण

3. उत्तराखण्ड राजस्व लेखापरीक्षा नियम संग्रह के दो भाग हैं, नियम संग्रह के विभिन्न भागों का विवरण निम्नलिखित है :-

#### लेखापरीक्षा नियम संग्रह

उत्तराखण्ड राजस्व लेखा परीक्षा नियम संग्रह भाग—I

- लेखापरीक्षा के समस्त चरणों का विस्तृत यथा लेखा परीक्षा कार्य योजना, लेखापरीक्षा सम्पादन, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग और प्रलेखन, लेखापरीक्षा अनुवर्ती, अनुपालन और लेखापरीक्षा किए जाने हेतु जांच सूची जिसके द्वारा माल सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प एवं निबंधन, आबकारी, भूविज्ञान और खनन और वन विभागों की राजस्व लेखापरीक्षा संपादित किए जाने के लिए प्रयोग किया जायेगा।

राज्य में राजस्व अर्जन विभागों जिनके द्वारा राज्य के कुल राजस्व में मुख्य योगदान है, संबंधित विभागों को पृथक—पृथक भागों से विभक्त किया गया है। इन खंडों के अन्तर्गत यथा विभाग का परिचय, विनियामक ढांचा, राजस्व के स्रोत एवं प्रचलित

अधिनियम एवं नियम के लागू प्रावधानों एवं राजस्व लेखापरीक्षा के लिए चेकलिस्ट सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड  
राजस्व  
लेखापरीक्षा  
नियम संग्रह  
भाग -II

इस भाग में केवल महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अधिनियम, नियमों के प्रासंगिक प्रावधान हैं, जिसके द्वारा उपर्युक्त संबंधित विभाग के राजस्व लेखा परीक्षा को संचालित किए जाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राजस्व लेखा परीक्षा नियम संग्रह के मुख्य कार्य क्षेत्र

4. i राजस्व निर्धारण, राजस्व संग्रहण और प्रतिदायों के लिए विनियमों और क्रियाविधियों की राजस्व लेखा परीक्षा लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में –

- (क) करों, शुल्कों, प्रयोक्ता प्रभार एवं राजस्व संग्रहण के लिये निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उपयुक्त विनियम और क्रियाविधि बनाए जाने के लिए परीक्षण करना;
- (ख) उपयुक्त नमूना जाँच द्वारा विनियमों और क्रियाविधियों का वस्तुतः पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में प्रविष्टि की गई राशियों की शुद्धता के बार में भी परीक्षण किया जायेगा।

ii वसूलियों की आवधिकता की लेखा परीक्षा

ऐसे वित्तीय नियम या आदेश के प्रकरण जिसके द्वारा वसूलियों के लिए स्तर या आवधिकता निर्धारित की गई हो, ऐसे प्रकरणों में लेखापरीक्षा को यथासंभव यह परीक्षण करना चाहिए कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया गया है।

iii बकाया अतिदेयों का अवलोकन

लेखापरीक्षा को किसी भी प्रकार के बकाया देय की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए तथा विभागीय प्राधिकारियों को उनकी वसूली के लिये संभव उपाय के बारे में सुझाव देना चाहिए। जब कोई देय अवसूलनीय हैं तो उनके अधित्यजन करने और समायोजन के लिए आदेश प्राप्त करने चाहिए।

**उत्तराखण्ड राजस्व ५. आन्तरिक नियंत्रणों की लेखापरीक्षा**

**लेखापरीक्षा द्वारा  
आन्तरिक नियंत्रणों  
की लेखा परीक्षा**

राजस्व लेखापरीक्षा को संपादित किए जाने के समय आन्तरिक नियंत्रण के परीक्षण करते समय लेखापरीक्षा दलों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

- i. विधि के अधीन माँग या प्रतिदाय की संगणना के लिए आवश्यक ऑँकड़ों का संग्रहण और उनका उपयोग
- ii. वर्तमान में लागू कर कानूनों के अनुसार विभिन्न करों, फीस, किराया, रायल्टी आदि की संगणना और वसूली
- iii. माँगों, संग्रहण और प्रतिदायों का नियमित लेखाकरण
- iv. अपेक्षित एवं अनुरूप अभिलेखों को यथोचित रूप से तैयार किया जाना।
- v. करों के उद्ग्रहण या संग्रहण या प्रतिदायों को प्राधिकृत करने की लापरवाही या चूक करने के प्रति सुरक्षा के उचित प्रबंध किये गये हैं।
- vi. अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए मशीनरी पर्याप्त है,
- vii. दोहरे प्रतिदायों, प्रतिदाय के जाली या झूठे आदेश या जालसाजी, चूक या गलती से होने वाले राजस्व की अन्य प्रकार की हानि शीघ्र ध्यान में लाये जाने और उनकी जाँच पड़ताल किया जाए।
- viii. कर दाताओं के दावों का तत्परता से परिशीलन किया जाता है और पर्याप्त औचित्य और उचित प्राधिकार के बिना उनका परित्याग या उन्हें कम नहीं किया जाता है।
- ix. न्यायालय में या अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अनिर्णीत मामले पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जा रही है और अपीलें जहाँ औचित्य है या आवश्यक मानी गयी है, को सीमा अवधि के अन्दर दायर किया गया है।
- x. राजस्व के प्राक्कलनों की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वसूली प्राक्कलन के अनुरूप की गयी है।

साधारणतया लेखापरीक्षा विभाग यह देखेगा कि आन्तरिक क्रियाविधि माँगों, संग्रहण और प्रतिदायों को सही और नियमित रूप से लेखाबद्ध करने को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करती हैं और कि पर्याप्त कारण के बिना सरकार को देय कोई भी राशि उसकी पुस्तकों में बकाया न रहे और दावों का तत्परता से परिशीलन किया जाता है उचित प्राधिकार के बिना उसका परित्याग या उन्हें कम न किया जाना है।

आज्ञा से,  
एस०एन० पाण्डे,  
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 197/XXVII(6)/1466/Three/2022, dated October 28, 2022 for general information:

No. 197/XXVII(6)/1466/Three/2022  
Dated Dehradun, October 28, 2022

#### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 20 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 2 of 2012) and rule 6 and clause (b) of rule 7 of Uttarakhand Internal Audit Manual 2021 read along with the Standards to be applicable for Institute of Internal Auditors and International Supreme Audit Institution (INTOSAI) to implement standards for Revenue Audit, Guidelines with complete steps for conducting Risk-Based internal audit for Revenue Audit as per with respective principles and Standards to be adopted, the Governor is pleased to allow to following manual, namely: -

#### **The Uttarakhand Revenue Audit Manual, 2022**

<b>Short title,</b>	1. (1) This audit manual may be called the Uttarakhand Revenue Audit Manual, 2022.
<b>extent and</b>	(2) (i) These audit manuals shall apply to all the auditees notified under the Gazette Notification No. 495/XXVII(11)/2012 dated 26 November 2012 as per the provision of sub- section (1) of section 4 of the Uttarakhand Audit Act 2012.
<b>Commencement</b>	

(ii) Audit of receipts includes the audit of all taxes and non-tax receipts of Uttarakhand State Government.

(iii) The Directorate of Audit by the personnel and officers or Chartered Accountant firms or institute/agencies empaneled by the Finance Department from time to time for the Directorate of Audit shall carry out audit through this audit manual while auditing such revenue departments.

(iv) This shall be read with the Uttarakhand Internal Audit Manual 2021 and other audit manuals prepared for specific areas such as Performance Audit Manual, Fraud, and Forensic Audit Manual, Information Technology Audit Manual.

(v) This mainly focuses on the audit of receipts with reference to levy, collection, evasion, the pursuit of claims, assessment, examine internal controls, refund, rebates, and other relevant areas for a revenue generating departments.

(3) This shall come in force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

**Main  
Objectives of  
Revenue Audit**

2. The main objectives of the Revenue Audit are as follows –

(i) adequate regulations and internal procedures are in place to ensure an effective check on the assessment, collection of the revenues.

(ii) the applicable regulations and procedures have been implemented and adopted by the departments.

(iii) the department has assessed, collected, and accounted for the revenues on time in line with the provisions of the Act and rules.

(iv) the refunds and exemptions provided in line with the provisions of the Acts and rules/manuals.

(v) assessment of Internal Control of Revenue Generating Department

(vi) use of modern technologies by the revenue department and use of General and IT Controls for such modern technologies

**Uttarakhand Revenue Audit Manual Parts** 3. Uttarakhand Revenue Audit Manual has two parts, the detail of two parts of audit manual are mentioned below

**and brief description of its parts**

<b>Uttarakhand Revenue Audit Manual-Part-I</b>	<p>Detailed audit process covering the entire audit phases viz. audit planning, audit execution, audit reporting &amp; documentation, audit follow up, compliance and audit checklists to be used in conducting revenue audit of the Goods and Service Tax(GST), Value Added Tax (VAT), Excise, Stamp &amp; Registration, Geology &amp; Mining and Forest Departments.</p> <p>The revenue departments that are contributing to the major share in total revenue of the state have been segregated in different sections. These departments have divided into various sections. These Sections includes viz. introduction to the department, regulatory framework, and applicable provisions of the Act and rules and checklist for revenue audit</p>
<b>Uttarakhand Revenue Audit Manual-Part-II</b>	<p>This volume merely covers important definitions and relevant provisions of the Act and rules that need to be applied in conducting revenue audit of the respective department mentioned above.</p>

**Area of operating Uttarakhand Revenue Audit Manual**

4. **Audit of regulations and procedures for assessment, collection, and refunds**

The most important function of audit is

- (a) Examination of adequate regulations and that have been framed by the Revenue Departments to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of taxes, fees, user charges or any other mechanism for revenue collection;
- (b) adequate test check that such regulations and procedures are being adhered to. Audit should also make such examination as in respect to the correctness of the sums brought to account.

#### **ii. Audit of periodicity of recoveries**

Where any financial rule or order applicable to the case prescribes the scale or periodicity of recoveries, the Audit will as far as possible examine that there is no deviation therefrom without proper authority.

#### **iii. Examination of outstanding dues**

Audit should carefully review any outstanding dues and suggest to the departmental authorities any feasible means for their recovery. Whenever any dues are irrecoverable, orders for their waiver and adjustment should be sought.

**Uttarakhand  
Revenue  
Audit  
Manual for  
audit of  
Internal  
Control**

#### **5. Audit of Internal Control**

During examination of the internal controls the following points shall be taken into consideration by the audit parties while conducting Revenue Audit

- i. collection and utilization of data necessary for the computation of the demand or refund under laws;
- ii. computation and realization of various taxes, fees, rents, royalty, etc. are in accordance with the existing applicable tax laws;
- iii. the regular accounting of demands, collections, and refunds;
- iv. that the relevant and requisite records are being maintained properly;

- v. that adequate control and monitoring mechanisms have been devised to prevent loss or leakage of revenue;
- vi. that the machinery for detection of cases of evasion is adequate;
- vii. double refunds, fraudulent or forged refund orders or other losses of revenue through fraud, default or errors are promptly brought to light and their investigation;
- viii. that claims of taxpayers are pursued with due diligence and are not abandoned or reduced except with adequate justification and proper authority;
- ix. that cases pending in courts or before appellate authorities have been pursued adequately and appeals, wherever justified or considered necessary, have been filed within the period of limitation; and
- x. that the estimates of revenue have been realized at the end of the financial. Fees, user charges or to authorize refunds;

Generally Audit department shall see that the internal procedures ensure correct and regular accounting of demands, collections, and refunds and that no amounts due to Government remain outstanding in its books without sufficient reason and that the claims are pursued with due diligence and are not abandoned or reduced except with adequate justification and with proper authority.

By Order,  
S.N. PANDEY,  
Secretary.